

Bazars in Delhi as compared to the prices prevailing on the 1st July, 1976; and

(b) if so, what are the reasons therefor ?]

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पहली जुलाई, 1976 और 9 अगस्त, 1976 के बीच दिल्ली में सुपर बाजारों द्वारा बेची गई दालों के मूल्यों में मिला-जुला रुख रहा है। साबुत मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, काले मसूर और लाल मसूर के मूल्य 2% से 6% के बीच कम किये गये हैं। साबुत उड़द की दाल, अरहर की दाल, काले चने और चने की दाल के मूल्य वही थे। तथापि, धुली मूंग, धुली उड़द और छिलके वाली उड़द के मूल्य बढ़े हैं।

(ख) धुली मूंग, धुली उड़द और छिलके वाली उड़द के मूल्य बरसात के मौसम में उनकी प्रोसेसिंग करने में आने वाली कठिनाइयों की वजह से उनकी सप्लाई में हुई कमी से बढ़े हैं।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI A. C. GEORGE) : (a) There has been a mixed trend in the prices of pulses sold by Super Bazars in Delhi, between 1st July, 1976 and 9th August, 1976. The prices of Dal Moong Whole, Dal Moong Chilka, Masoor Black and Masoor Red have been reduced by 2% to 6%. The prices of Dal Urad Whole, Dal Arhar, Gram Black and Dal Gram were the same. There was, however, a rise in the prices of Moong Washed, Urad Washed and Urad Chilka.

(b) The increase in the prices of Moong Washed, Urad Washed and Urad Chilka is on account of reduced supplies due to difficulties encountered in processing them during the rainy season.]

महाराष्ट्र में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले

179. श्री बापूरावजी माहतरावजी बेशमुख : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन जिलों के औद्योगिक विकास पर कितनी धन-राशि खर्च की गई और उस में केन्द्रीय सरकार का कितना हिस्सा रहा;

— (ग) क्या यह सच है कि वर्धा जिले के निवासियों ने उस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

*[Industrially backward districts in Maharashtra

179. SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of districts in Maharashtra which have been declared industrially backward;

(b) the amount spent for industrial development in these districts during the last three financial years and the Central Government's contribution in this regard;

(c) whether it is a fact that the residents of Wardha had represented to Government to declare that district as industrially backward; and

(d) if so, what action Government have taken in the matter ?]

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) महाराष्ट्र के निम्नलिखित 13 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुना गया है जो रियायती दर पर वित्तीय सुविधाएं पाने के योग्य हैं :—

1. औरंगाबाद
2. भंडारा
3. भीर
4. बुलढाना
5. चन्द्रपुर

6. कोलाबा
7. भूलिया
8. जलगांव
9. नान्देड़
10. ओसमानाबाद
11. परभनी
12. रत्नागिरि और
13. यवतमाल।

इनमें से 3 जिले जैसे रत्नागिरि, औरंगाबाद तथा चन्द्रपुर को राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय राज सहायता योजना के अन्तर्गत भी हकदार चुना गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्यक्ष केन्द्रीय अनुदान/राजसहायता के संबंध में केन्द्र सरकार से आंशिक सहायता पाने के लिए महाराष्ट्र को 2,47,40,870 रु० की धनराशि दी गई है। राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी धनराशि के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) मार्च, 1971 में वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इण्डस्ट्रीज यूनियन लि० के अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री को वर्धा जिले की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुने जाने के लिये एक अभ्यावेदन भेजा गया था जिसके उत्तर में वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इण्डस्ट्रीज यूनियन लि० के अध्यक्ष को सूचित किया गया था कि वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त पाने के योग्य बनने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला चुनने के प्रयोजन से अपनाई गई कसौटी के आधार पर वर्धा जिले को इस प्रयोजन के लिए नहीं चुना गया है।

†[THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI T. A. PAI): (a) The following 13 districts of Maharashtra have been selected as industrially backward to qualify for concessional finance facilities:

1. Aurangabad
2. Bhandara
3. Bhir
4. Budhana
5. Chandarpur
6. Colaba
7. Bhulia
8. Jalgaon
9. Nanded
10. Osmanabad
11. Prabhani
12. Ratangiri
- and
13. Yeotmal.

From out of these, on the basis of the proposals of the State Government, the three districts of Ratnagiri, Aurangabad and Chandrapur have been selected to qualify also for the Central Subsidy Scheme.

(b) Central Government's contribution in favour of Maharashtra towards Central Outright Grant/Subsidy during the last three financial years amounts to Rs. 2,47,40,870. Information regarding amount spent by State Government in this regard is not readily available.

(c) and (d) A representation for selection of Wardha district as industrially backward was addressed in March, 1971 to the then Minister of Finance by the President, Wardha District Cooperative Industries Union Ltd., Wardha. In reply, the President, Wardha District Cooperative Industries Union Ltd., was informed that on the basis of the criteria adopted for the purpose of selection of industrially backward districts to qualify for concessional finance from financial institutions, the District of Wardha has not been selected for the purpose.]

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

180. श्री बापूरावजी मारुतरावजी देशमुख : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बड़े पैमाने पर भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारगर्भित है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†[Proposal to set up heavy industries in Wardha district of Maharashtra

180. SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up heavy industries on a large scale in Wardha district of Maharashtra; and